



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2016/आषाढ़ 31, 1938

No. 302]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ASADHA 31, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 14 जुलाई, 2016

सं. टीएएमपी/8/2013/-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, कोलकाता पत्तन न्यास की विद्यमान दर मानों की वैधता अवधि को बढ़ाते हैं, जैसाकि इसके साथ संलग्न आदेश में विनिर्दिष्ट है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

संख्या. टीएएमपी/8/2013-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

आवेदक

कोरम

- (i) श्री टीएस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जुलाई, 2016 के 5वें दिन को पारित)

यह मामला कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) की विद्यमान दर मानों (एसओआर) की वैधता अवधि को बढ़ाने से संबंधित है।

2.1 केओपीटी की विद्यमान दर मानों को विगत में इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/8/2013-केओपीटी दिनांक 21 फरवरी, 2014 द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश भारत के राजपत्र में 19 मई, 2014 को अधिसूचित किया गया था। इस आदेश में केओपीटी के दर मानों की वैधता की अवधि 31 मार्च, 2016 तक निर्धारित की गई है।

2.2 उसके पश्चात्, केओपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा केओपीटी के दर मानों की वैधता अवधि को 30 जून, 2016 तक बढ़ा दिया है। केओपीटी को उक्त आदेश द्वारा अपना सामान्य संशोधन प्रस्ताव 30 अप्रैल, 2016 तक प्रस्तुत करने की सलाह भी दी गई थी।

3. तत्पश्चात्, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 20 मई 2016 द्वारा प्रशुल्क नीति, 2015 के अंतर्गत अपने दर मानों में सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर संबंधित उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठन के साथ परामर्श किया गया है। इस प्रस्ताव के संबंध में केओपीटी से अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांगे जाने की दृष्टि से जांच की जा रही है। इस मामले में एक संयुक्त सुनवाई का अभी आयोजन किया जाना है।

4. यह बात दोहरायी जाती है कि पोत परिवहन मंत्रालय ने जनवरी, 2005 में तत्कालीन एमएसआरटीएच द्वारा जारी तटीय रियायत नीति में आंशिक संशोधन करते हुए अपने पत्र दिनांक 17 सितम्बर, 2015 द्वारा इस प्राधिकरण को निदेश जारी किए थे। पोत परिवहन मंत्रालय के 17 सितम्बर, 2015 के पत्र के अनुसार, तटीय पोतों और तटीय कंटेनरों के लिए पोत संबंधी प्रभारों और कंटेनर संबंधी प्रभारों के संबंध में भारतीय रुपए **प्रति** अमरीकी \$ की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि सभी तटीय पोतों के लिए पोत से संबंधित प्रभार और सभी तटीय कंटेनरों के लिए कंटेनर संबंधी प्रभार, इसी प्रकार के प्रभारों के 60% से अधिक न हो। पोत परिवहन मंत्रालय के इन निर्देशों को इस प्राधिकरण के आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 द्वारा अवगत कराया गया था। तथापि, पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने बाद के पत्र दिनांक 11 मई, 2016 द्वारा अपने दिनांक 17 सितम्बर 2015 में दिए गए पूर्व के निर्देशों को आस्थगित रखने के निदेश दिए हैं। इसलिए, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2015 को भी आस्थगित रखने के लिए एक कॉमन आदेश दिनांक 19 मई, 2016 पारित किया है। उक्त आदेश केओपीटी सहित सभी महापत्तन न्यासों को अग्रेषित किया गया है।

5. इस पृष्ठभूमि में, केओपीटी ने अपने पत्र एफआईएन/162/बी दिनांक 21 जून, 2016 द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र संख्या 8(15)/2015-टीएएमपी दिनांक 11 मई, 2016 द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर अद्यतन की गई पहले ही प्रस्तुत संशोधित दर मानों के मसौदे के आधार पर संशोधित दर मानों की अधिसूचना के जारी होने तक केओपीटी की विद्यमान दर मानों (विशेष दर सहित) की वैधता की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है और इसे न्यासी मंडल के विचार एवं अनुमोदन के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। केओपीटी ने यह भी उल्लेख किया है कि संशोधित दर मानों का मसौदा केओपीटी की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है, जिसके द्वारा पत्तन उपयोक्ताओं की टिप्पणियां पुनः आमंत्रित की गई हैं और यह भी उल्लेख किया है कि अद्यतन दर मानों का मसौदा और विधिवत रूप से पूर्ण आवश्यक प्रपत्र, बोर्ड के संकल्प के साथ अलग से भेजे जाएंगे।

6.1 जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, केओपीटी ने अपने पत्र में केओपीटी के कर्मचारियों, जो पहली अप्रैल, 2004 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे, के संबंध में पेंशन संबंधी देयता के संवहन के लिए केओपीटी को समर्थ बनाने के लिए 5% की विशेष लेवी का विस्तार करने का भी अनुरोध किया है। विशेष दर केओपीटी के दर मानों की वैधता की अवधि के दौरान प्रभारित की जानी है। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि उपर्युक्त 5% की विशेष लेवी (भाग-I से भाग-VIII के अंतर्गत दर मानों में अधिसूचित विभिन्न प्रभारों के आधार पर) फरवरी, 2014 में केओपीटी के प्रशुल्क के गत सामान्य संशोधन के दौरान, अनुमोदन करते समय, इस प्राधिकरण ने यह नोट किया कि वर्ष 2010 में केओपीटी के प्रशुल्क की समीक्षा के दौरान, पेंशन लेवी का अनुमोदन किया गया था, जो केओपीटी द्वारा तीन प्रशुल्क चक्रों की अवधि के दौरान वसूल की जानी थी। इस बात पर विचार करते हुए कि अंतिम प्रशुल्क चक्र व्यतीत हो गया है, निधियों में आयी कमी को शेष दो प्रशुल्क चक्रों में वसूल किया जाना था। चूंकि उस समय

केवल दो वर्ष अर्थात् 2014-15 और 2015-16 (दूसरे प्रशुल्क चक्र में) ही शेष थे, इसलिए, निधियों में कमी को दो वर्षों की अवधि के लिए विशेष लेवी के माध्यम से बूझल करने का निर्णय लिया गया था।

6.2 यह भी देखा जा सकता है कि गत प्रशुल्क चक्र के पश्चात् अर्थात् तीसरे प्रशुल्क चक्र की बढ़ायी गई अवधि के दौरान विशेष लेवी की भी वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

7.1 चूँकि केओपीटी के दर मानों की वैधता की अवधि 30 जून, 2016 को समाप्त हो गई है, इसलिए, केओपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित समय पर विचार करते हुए और केओपीटी के दर मानों में शून्य की स्थिति से बचने के उद्देश्य से केओपीटी के विद्यमान दर मानों और विशेष दर की वैधता की अवधि को 30 जून, 2016 के पश्चात बढ़ाना उपयुक्त समझा गया है।

7.2 उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्राधिकरण द्वारा केओपीटी के विद्यमान दर मानों, विशेष लेवी सहित, की वैधता अवधि 30 सितम्बर, 2016 तक अथवा संशोधित दर मानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ायी जाती है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./143/16(184)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 14th June, 2016

No. TAMP/8/2013-KOPT.— In exercise of the powers conferred under Section 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of Kolkata Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/8/2012- KOPT

The Kolkata Port Trust

- - -

Applicant

QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 5th day of July, 2016)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of Kolkata Port Trust (KOPT).

2.1 The existing SOR of the KOPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/8/2013-KOPT dated 21 February, 2014. This Order was notified in the Gazette of India on 19 May, 2014. The Order prescribed the validity of the SOR of KOPT till 31 March, 2016.

2.2 Thereafter, based on the request made by KOPT, this Authority has extended the validity of SOR of KOPT up to 30 June, 2016 vide Order dated 30 March, 2016. The KOPT was also advised vide the said Order to file its general revision proposal by 30 April, 2016.

3. Thereafter, the KOPT vide its letter dated 20 May, 2016 has filed its proposal for general revision of its Scale of Rates under Tariff Policy, 2015. The proposal has been taken up on consultation with the relevant users/user organization. The proposal is under examination for seeking additional information/clarification from KOPT. A joint hearing in this case is yet to be scheduled.

4. It may be recalled that the MOS vide its letter dated 17 September, 2015 had issued a direction to this Authority partially modifying the coastal concession policy issued by the (then) MSRTH in January 2005. As per the letter dated 17 September, 2015 of the MOS, vessel related charges and container related charges for coastal vessels and coastal containers should take into account the exchange rate fluctuation of Indian Rupee vis-à-vis the US \$ so that vessel related charges for all coastal vessels and the container related charges for all coastal containers should not exceed 60% of the corresponding charges. This direction of the MOS was communicated by this Authority by an Order dated 5 October, 2015. However, the MOS vide its subsequent letter dated 11 May, 2016 has directed to keep its earlier direction dated 17 September, 2015 in abeyance. Therefore, this Authority has passed a Common Order dated 19 May, 2016 to keep its Order dated 5 October, 2015 also in abeyance. The said Order has been forwarded to all the Major Port Trusts including KOPT.

5. In this backdrop, the KOPT vide its letter dated Fin/162/B dated 21 June, 2016 has requested to extend the validity of the existing SOR of KOPT (including Special Rate) till notification of revised SOR, on the ground that the draft Scale of Rates which was submitted earlier has been updated based on the direction issued by the Ministry of Shipping vide its letter no. 8(15)/2015-TAMP dated 11 May, 2016 and is being placed for consideration and approval of the Board of Trustees. The KOPT has also stated that the draft revised SOR is being hosted in the website of KOPT inviting fresh comments of the port users and that the draft updated Scale of Rates along with necessary forms, duly filled in along with Board Resolution will be sent separately.

6.1 As stated above, the KOPT in its letter has also requested to extend the special levy of 5% to enable the KOPT to meet the pension liability in respect of employees of KOPT who have retired prior to 1 April, 2004. The special rate is to be levied during the validity of the Scale of Rates of KOPT. It is relevant hereto mention that while approving the said special levy of 5% (on various charges notified in the Scale of Rates under Part – I to Part – VIII) during the last general revision of tariff of KOPT in February 2014, this Authority had noted that during the review of tariff of KOPT in the year 2010, the pension levy was approved to be recovered by the KOPT over a period of three tariff cycles. Considering that the last tariff cycle is over, the shortfall in the fund position then had to be recovered in the remaining two tariff cycles. Since only two balance years i.e. 2014-15 and 2015-16 (in the second tariff cycle) was available then, the shortfall in the fund was decided to be recovered by way of a special levy for a period of two years.

6.2 It can be seen that, there appears to be a need to extend the validity of the Special Levy also beyond the last tariff cycle i.e. during the extended tariff validity period of the third tariff cycle.

7.1 Since the validity of SOR of KOPT expires on 30 June, 2016 and considering the time required for processing the proposal filed by the KOPT and in order to avoid a vacuum in the SOR of KOPT, it is felt appropriate to extend the validity of the existing SOR and Special rate of KOPT beyond 30 June, 2016.

7.2 In view of the above, this Authority extends the validity of the existing SOR of KOPT including the special levy up to 30 September, 2016 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/16(184)]